सहकारिता विभाग

20. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वेजफेड के त्रि–स्तरीय सहकारी श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के उद्देश्य से पंचायत स्तरीय संग्रहण केंद्रों की स्थापना, प्रखंड स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण, संघो एवं समितियों को कार्यशील पूंजी की उपलब्धता तथा रिफर वाहन हेतु कुल राशि 1,06,39,24,750 (एक अरब छह करोड़ उनतालीस लाख चौबीस हजार सात सौ पचास) रू० मात्र की योजना की स्वीकृति एवं योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में 45,50,80,880 (पैंतालीस करोड़ पचास लाख अस्सी हजार आठ सौ अस्सी) रू० मात्र के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। **20. स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

21. बिहार राज्य सहकारिता नीति, 2026 की स्वीकृति। **21. स्वीकृत।**

सहकारिता विभाग

22. रैयाम (दरभंगा) एवं सकरी (मधुबनी) में बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर नयी सहकारी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (byproducts) आधारित अन्य इकाईयों की स्थापना तथा परिचालन इंडियन पोटाश लि० (IPL), नई दिल्ली द्वारा करने तथा बैंक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर स्वीकृत परियोजना लागत का 40% वित्तीय सहायता प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

23. बिहार के 19 न्यायमंडलों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत लंबित वादों के त्वरित निष्पादन हेतु अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के एक–एक पद कुल 19 (उन्नीस) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

24. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा–3 के अन्तर्गत पटना में अतिरिक्त 02 (दो) एवं मुजफ्फरपुर में अतिरिक्त 01 (एक) विशेष न्यायालयों के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के कुल 03 (तीन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **24. स्वीकृत।**